

## 2015 का विधेयक सं.16

### राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

ऊंट के वध के प्रतिषेध हेतु उपबंध करने और उसके राजस्थान से अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "ऊंट का मांस" से ऊंट का मांस अभिप्रेत है;

(ख) "ऊंट" से ऊंटीय प्रजाति का कोई पशु अभिप्रेत है;

(ग) "संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) अभिप्रेत है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी अन्य अधिकारी आता है जिसे राज्य सरकार के द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों और ऐसी कालावधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सक्षम

प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये;

- (ड) "खण्ड आयुक्त" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कोई आयुक्त अभिप्रेत है;
- (च) "निर्यात" से राजस्थान राज्य से, राजस्थान राज्य के बाहर के किसी भी अन्य स्थान को ले जाया जाना अभिप्रेत है;
- (छ) "दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र" से दुर्भिक्ष या अभाव से ग्रस्त ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत होगा जिसके बारे में राज्य सरकार के द्वारा किसी समुचित विधि के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई घोषणा की गयी है;
- (ज) "वध" से किसी भी ढंग से और चाहे किसी भी प्रयोजन के लिए, साशय मारना अभिप्रेत है;
- (झ) "परिवाहक" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है,-
- (क) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) में यथापरिभाषित किसी माल गाड़ी के मामले में,-
- (i) स्वामी, यदि बुकिंग उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये;
  - (ii) यान का तत्समय प्रभारी व्यक्ति;
  - (iii) माल या पशुधन की बुकिंग का तत्समय प्रभारी व्यक्ति;

- (iv) प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक या मुख्य कार्यपालक या, यथास्थिति, कारबार का प्रभारी कोई भी अन्य व्यक्ति (जहां स्वामी कोई कम्पनी हो) जब बुकिंगें उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जायें;
- (v) किसी भागीदारी फर्म के मामले में भागीदार, जब बुकिंग उसके अनुदेश के अधीन या उसकी जानकारी से की जाये;
- (ख) रेल माल गाड़ी के मामले में,-
- (i) किसी रेल स्टेशन पर माल और पशुधन की बुकिंग का तत्समय प्रभारी व्यक्ति; और/या
- (ii) ऐसा व्यक्ति, जो किसी रेल स्टेशन पर रेल रसीदें तैयार करता है;
- (ग) ऐसा परेषिती जिसे पशुधन परिदत्त किया जाना है; और
- (घ) किसी भी अन्य मामले में, पशुधन का वहन करने वाला या उसके साथ जाने वाला व्यक्ति।

**3. ऊंट के वध का प्रतिषेध.-** तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी प्रथा या रूढ़ि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंट का वध नहीं करेगा या नहीं करवायेगा या उसे वध के लिए प्रस्थापित नहीं करेगा या नहीं करवायेगा।

**4. ऊंट का मांस और ऊंट मांस के उत्पादों के कब्जे, विक्रय या परिवहन का प्रतिषेध.-** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कोई भी व्यक्ति ऊंट का मांस या किसी भी रूप में ऊंट मांस के उत्पादों का कब्जा, विक्रय या विक्रय के लिए परिवहन नहीं करेगा या विक्रय या परिवहन नहीं करवायेगा।

**5. वध के प्रयोजन के लिए ऊंट के निर्यात का प्रतिषेध और अन्य प्रयोजनों के लिए अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन.-** (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंट का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर या अपने निमित्त कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति के जरिये, वध के प्रयोजनों के लिए या यह जानकारी होते हुए कि उसका वध किया जा सकता है या किया जाना संभाव्य है, राज्य के भीतर के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को निर्यात नहीं करेगा और निर्यात नहीं करवायेगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजस्थान के दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों से ऊंट का किसी विधिमान्य परमिट के अधीन चराई के प्रयोजनों के लिए भारत में के अन्य राज्यों में अस्थायी प्रव्रजन, विहित और इसमें आगे अधिकथित रीति से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) किसी भी दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्र में निवास करने वाला और किसी ऊंट का प्रव्रजन चाहने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को, ऊंटों की संख्या और उस राज्य या उन राज्यों के नाम, जिसमें या

जिनमें प्रव्रजन प्रस्तावित है और ऐसी कालावधि, जिसके लिए परमिट अपेक्षित है, के सहित, प्रस्तावित प्रव्रजन के आवश्यक होने की परिस्थितियों का कथन करते हुए आवेदन करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात्, विहित प्ररूप में और रीति से उसे कोई परमिट मंजूर कर सकेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऊंट के राज्य से बाहर ऐसा अस्थायी प्रव्रजन अनुज्ञात किये जाने के पूर्व पहचान चिह्न लगाये जाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा और किसी भी मामले में उक्त प्रव्रजन की कालावधि परमिट की मंजूरी की तारीख से ठीक अगले अगस्त मास से परे की नहीं होगी।

(5) ऐसे अस्थायी प्रव्रजन से लौटने पर उप-धारा (3) में निर्दिष्ट आवेदक सक्षम प्राधिकारी को अपने द्वारा वापस लाये गये ऊंटों की संख्या के बारे में लिखित सूचना, फेरफारों के, यदि कोई हों, स्पष्टीकरण के साथ, देगा।

(6) यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे ऊंट राज्य में, और परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर, वापस नहीं लाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

(7) सक्षम प्राधिकारी कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए राजस्थान से ऊंट के निर्यात के लिए विहित रीति से विशेष परमिट जारी कर सकेगा और ऐसी अनुज्ञा मंजूर करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से ऐसे ऊंटों की संख्या किसी भी

रीति से स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम न हो जाये।

(8) उप-धारा (4), उप-धारा (6) या उप-धारा (7) के अधीन किये गये सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कोई भी आवेदक या उप-धारा (7) के अधीन विशेष परमिट चाहने वाला, कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर खण्ड आयुक्त को आवेदन कर सकेगा और खण्ड आयुक्त ऐसे आवेदन पर या स्वप्रेरणा से किसी भी आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे और ऐसा आदेश अंतिम तथा निश्चयक होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

**6. परिवाहक का दुष्प्रेरक होना.-** जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने के उद्देश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से ऊंटों का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपबंधित है।

**7. अभिगृहीत ऊंट की अभिरक्षा और निपटारा.-** (1) जब कभी तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप या निरीक्षण के परिणामस्वरूप या अन्यथा ऊंट अभिगृहीत किये जायें तो अभिगृहीत किये गये ऊंटों की अभिरक्षा, मामले का अंतिम

निपटारा होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी को सौंपी जा सकेगी:

परन्तु जहां किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्वैच्छिक एजेन्सी नहीं हो, वहां सक्षम प्राधिकारी ऊंटों की अभिरक्षा क्षेत्र के बाहर की किसी भी ऐसी एजेन्सी या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंप सकेगा जो ऐसे पशुओं को स्वेच्छा से रखना चाहे।

(2) जब कभी कोई मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाये तो ऊंटों की अभिरक्षा या स्थायी रूप से सौंपे जाने के बारे में आगे के आदेश सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किये जायेंगे जो उचित समझी जायें।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर उसके विरुद्ध खण्ड आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(4) ऐसी अपील पर खण्ड आयुक्त अपीलार्थी और सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निपटारा होने तक आदेश के रोक दिये जाने का निदेश दे सकेगा या आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या बातिल कर सकेगा और ऐसे कोई भी और आदेश कर सकेगा जो न्यायसंगत हों।

(5) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई भी ऊंट अभिगृहीत किया जाये तो सक्षम प्राधिकारी या खण्ड आयुक्त को,

ऐसे पशु के कब्जे, परिदान, निपटारे या छोड़े जाने के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को अधिकारिता नहीं होगी।

**8. शास्ति.-** (1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई धारा 4 या धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

**9. उपहति कारित करने के लिए दण्ड.-** (1) जो कोई किसी भी ऊंट को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति कारित करता है।

(2) जो कोई किसी ऊंट को साशय उपहति कारित करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।



(3) जो कोई उप-धारा (2) के अधीन किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है।

#### 10. किसी भी ऊंट को साशय क्षति पहुंचाने के लिए दण्ड.-

(1) जो कोई किसी ऊंट को साशय गंभीर क्षतियां कारित करता है वह, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो सात हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजन के लिए गंभीर क्षति के अन्तर्गत है-

- (i) पुंसत्वहरण (नर ऊंट के मामले में),
- (ii) किसी भी आँख को स्थायी रूप से दृष्टिहीन करना,
- (iii) किसी भी कान को स्थायी रूप से श्रवण शक्तिहीन करना,
- (iv) किसी भी अंग या जोड़ को अलग करना,
- (v) किसी हड्डी या दांत का भंग या विस्थापन,
- (vi) कोई भी ऐसी उपहति, जो जीवन को खतरे में डाले या जो उपहत को घोर शारीरिक कष्ट कारित करे और अन्ततः अनुपयुक्त या अनुपयोगी बना दे।

(2) जो कोई-धारा (1) के अधीन के किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी

होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध के लिए उपबंधित है।

**11. सबूत का भार.-** जहां किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन के किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाये वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपराध नहीं किया था।

**12. स्थानों में प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति.-** (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को (जिसे इस धारा में इसके आगे "प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी जहां सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन का कोई अपराध किया गया है या किया जाना संभाव्य है।

(2) ऐसे स्थान का अधिभोगी प्रत्येक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति की उस स्थान में पहुंच को अनुज्ञात करेगा जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो और सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा उससे पूछे गये किसी प्रश्न का उत्तर अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार देगा।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति इस धारा

के अधीन किसी स्थान में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने में यावत्शक्य, किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी स्थान की तलाशी या निरीक्षण से संबंधित, संहिता की धारा 100 के उपबंधों का अनुसरण करेगा।

**13. इस अधिनियम के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का लोक सेवक समझा जाना.-** इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले समस्त व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

**14. सदभावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण.-** किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेंगी, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की जायें या की जाने के लिए आशयित हों।

**15. नियम बनाने की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी

नियम में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

---

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 51क(छ), समस्त प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे जाने के लिए आदिष्ट करता है।

ऊंट, राज्य के मरुस्थलीय पारिस्थितिकी-तंत्र का एक आवश्यक भाग है और इसने प्रतिकूल मरुस्थलीय परिस्थितियों में मानव आबादी के अस्तित्व को बनाये रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्तमान में, ऊंट संकट में हैं और हाल ही में इनकी संख्या में अचानक अत्यधिक कमी होने के कारण, इनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए गम्भीर प्रयास किये जाने आवश्यक हैं।

ऊंटों और इनकी प्रजाति को साशय मारे जाने के अनेक मामले प्रकाश में आये हैं। यह भी देखा गया है कि राजस्थान राज्य से बड़ी संख्या में ऊंटों को, इनका वध किये जाने के प्रयोजन से, अन्य राज्यों में परिवाहित किया या ले जाया जाता है। राज्य में बार-बार अकाल और अभाव की परिस्थितियां, इस आशंका को और अधिक बढ़ने की ओर प्रवृत्त करती हैं। विद्यमान विधियां इस समस्या का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होने के कारण, कार्य में प्रयुक्त होने वाले पशु के रूप में भी ऊंट हमारी कृषिक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अवसंरचना का आधार है। गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों जैसेकि बायो गैस, के लिए बढ़ती जागरूकता के साथ, इन पशुओं के गोबर की आवश्यकता का, ग्रामीण आबादी के लिए ईंधन और खाद के रूप में उपयोगिता के अलावा, अतिरिक्त महत्व हो गया है। उपरोक्त कारकों को दृष्टिगत रखते हुए, बूढ़े ऊंटों को भी, यहां तक कि जब वे दूध देने या भारवाही पशु के रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रह जायें, अनुपयोगी या अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशी पदार्थों पर निर्भरता कम करके, और ऊंट की प्रजाति के इन पशुओं द्वारा जैविक क्रिया के

रूप में उत्पन्न की गयी प्राकृतिक और मृदा अनुकूल खाद के उपयोग द्वारा प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा और सुधार करके, और जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 51क(छ) में, ऐसे उपयोगी प्राणियों के प्रति दया भाव रखने के लिए परिकल्पित है, संविधान के पूर्वोक्त अनुच्छेद के भाव को क्रियान्वित करने के लिए, इन पशुओं के वध का सर्वथा प्रतिषेध किया जाना आवश्यक है।

ऊंटों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उपयोगिता और योगदान को देखते हुए, और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए, ऊंटों के वध का प्रतिषेध करने के लिए और साथ ही, ऐसे पशुओं के वध के प्रयोजन के लिए निर्यात का प्रतिषेध करने के लिए और ऊंट प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे पशुओं के निर्यात या अस्थायी प्रव्रजन को विनियमित करने के लिए, और उनसे लाभान्वित होने वाली जनता के हितों की सुरक्षा के अन्य प्रयोजनों के लिए भी साधारण हित में एक नयी विधि अधिनियमित की जानी है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

प्रभूलाल सैनी,  
प्रभारी मंत्री।

**संविधान के अनुच्छेद 304 के खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन  
महामहिम राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश।**

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (29) विधि/2/2014 दिनांक 22 मार्च,  
2015 प्रेषक: प्रभूलाल सैनी, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: विशिष्ट सचिव,  
राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के राष्ट्रपति महोदय ने राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात भारत के

संविधान के अनुच्छेद 304 के खण्ड (ख) के परन्तुक के अनुसरण में उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने का अनुमोदन किया है।

## प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को, ऊंटों के अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात के लिए परमिट या विशेष परमिट जारी करने की रीति विहित करने के लिए सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 15, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य और नैतिक प्रकृति का है और ब्यौरे मुख्यतः के विषयों से संबंधित है।

प्रभूलाल सैनी,  
प्रभारी मंत्री।



(Authorised English Translation)

**Bill No. 16 of 2015**

**THE RAJASTHAN CAMEL (PROHIBITION OF  
SLAUGHTER AND REGULATION OF TEMPORARY  
MIGRATION OR EXPORT) BILL, 2015**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A**Bill*

*to provide for prohibition of slaughter of camel and also to regulate temporary migration or export thereof from Rajasthan.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Camel (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 2015.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

**2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "camel meat" means flesh of camel;
- (b) "camel" means an animal of camelus genus;
- (c) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974);
- (d) "Competent Authority" means Collector of a District and includes any other officer who may be authorized in this behalf by the State Government by notification in the Official Gazette to exercise the powers and perform the functions of the Competent Authority under this Act or the rules made thereunder for such area or areas and for such period as may be specified in the notification;
- (e) "Divisional Commissioner" means a Commissioner appointed by the State Government under section 17

of Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956);

- (f) “export” means to take out of the State of Rajasthan to any other place out of the State of Rajasthan;
- (g) “famine and scarcity affected area” shall mean an area affected by famine or scarcity in respect of which a declaration has been made by the State Government under an appropriate law by a notification in the Official Gazette;
- (h) “slaughter” means intentional killing by any method and for any purpose whatsoever;
- (i) “transporter” means and includes,-
  - (a) in the case of a goods carriage as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988),-
    - (i) the owner, if the booking is undertaken under his instruction or with his knowledge;
    - (ii) the person for the time being incharge of the vehicle;
    - (iii) the person for the time being incharge of booking of goods or livestock;
    - (iv) the Managing Director, Executive Director, General Manager or Chief Executive or any other person incharge of business, as the case may be, (where the owner is a company) when the bookings are undertaken under his instruction or with his knowledge;
    - (v) the partner, in the case of a partnership firm, if the booking is undertaken under his instruction or with his knowledge;
  - (b) in the case of Railway Goods Train,-
    - (i) the person for the time being incharge of booking of goods and livestock at a Railway Station; and/or
    - (ii) the person who prepares Railway Receipts at a Railway Station;

- (c) the consignee to whom the livestock is to be delivered; and
- (d) in any other case, the person carrying or accompanying the livestock.

**3. Prohibition of slaughter of camel.-** Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in any usage or custom to the contrary, no person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter any camel.

**4. Prohibition of possession, sale or transport of camel meat and camel meat products.-** Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no person shall possess, sale or transport for sale or cause to be sold or transported camel meat or camel meat products in any form.

**5. Prohibition of export of camel for the purpose of slaughter and regulation of temporary migration or export for other purposes.-** (1) No person shall export and cause to be exported any camel himself or through his agent, servant or other person acting in his behalf from any place within the State to any place outside the State for the purposes of slaughter or with the knowledge that it may be or is likely to be slaughtered.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) temporary migration of camel from the famine and scarcity affected areas of Rajasthan may be allowed by the Competent Authority to other States in India for grazing purposes under a valid permit in the manner prescribed and hereinafter laid down.

(3) Any person residing in any famine and scarcity affected area and desiring migration of any camel shall apply to the Competent Authority having jurisdiction over such area stating the circumstances necessitating the proposed migration together with the number of camel and name of the State or States to which migration is proposed and the period for which the permit is required.

(4) The Competent Authority after satisfying itself about the genuineness of the request of the applicant referred in sub-section (3), may grant him a permit in the prescribed form and manner

which among other things may provide for affixing of identification mark before such temporary migration of camel is allowed out of the State and in no case the period of said migration shall extend beyond the month of August next following the date of grant of the permit.

(5) On return from temporary migration the applicant referred to in sub-section (3), shall inform the Competent Authority in writing about the number of camel brought back by him together with the explanation for variation, if any.

(6) If any person does not bring back such camel into the State and also within the period specified in the permit he shall be deemed to have contravened the provisions of sub-section (1).

(7) The Competent Authority may issue special permit in the prescribed manner for export of camel from Rajasthan for agricultural or dairy farming purposes or for participation in an animal fair, and before granting such permission the Competent Authority shall also ensure that such export in no way reduces the number of such camel below the level of actual requirement of the local area.

(8) Any applicant referred to in sub-section (3) or any person seeking special permit under sub-section (7), aggrieved by an order of the Competent Authority made under sub-section (4), sub-section (6) or sub-section (7) may make an application, within thirty days from the date of the order, to the Divisional Commissioner and the Divisional Commissioner may upon such application or *suo motu* call for and examine the record of the case for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of any order and may pass such order as it may deem just and proper and such order shall be final and conclusive and shall not be called in question in any civil court.

**6. Transporter to be abettor.-** Whenever the camels are transported by any means of transport in furtherance of the object of commission of any offence under this Act, the transporter shall be guilty of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided under section 8 of the Act for person committing the said offence.

**7. Custody and disposal of camel seized.-** (1) Whenever as a result of search or seizure or as a result of inspection or otherwise the camels are seized, the custody of the seized camels pending final disposal of the case may be entrusted by an order of the Competent Authority to any recognized voluntary agency working for the welfare of such animals:

Provided that where there is no such voluntary agency in any local area, the Competent Authority may entrust the custody of camels to any such agency outside the area or to any other suitable person, who volunteers to maintain such animals.

(2) Whenever any case is finally disposed of, further orders regarding custody or permanent entrustment of camel shall be made by the Competent Authority subject to such terms and conditions as may be deemed proper.

(3) Any person aggrieved by an order made under sub-section (1) or sub-section (2) may, within thirty days from the date of the said order, appeal against it to the Divisional Commissioner.

(4) On such appeal the Divisional Commissioner may after giving an opportunity to the appellant and the competent Authority or any other officer authorized by him in this behalf to be heard, direct the order to be stayed pending disposal of the appeal or may modify, alter or annul the order and make any further orders that may be just.

(5) Whenever any camel is seized under this Act the Competent Authority or the Divisional Commissioner shall have, and notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, any other Court, Tribunal or other Authority shall not have jurisdiction to make orders with regard to possession, delivery, disposal or release of such animal.

**8. Penalty.-** (1) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 shall, on conviction, be punished with a rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend to five years and with fine which may extend to twenty thousand rupees.

(2) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 4 or section 5 shall,

on conviction, be punished with the rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to three years and with fine which may extend to five thousand rupees.

**9. Punishment for causing hurt.-** (1) Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any camel is said to cause hurt.

(2) Whoever intentionally causes hurt to a camel shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to two years and with fine which may extend to three thousand rupees.

(3) Whoever abets the commission of an offence under subsection (2), shall be guilty of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided for the said offence.

**10. Punishment for intentionally injuring any camel.-** (1) Whoever intentionally causes grievous injuries to a camel shall, on conviction, be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend to three years and with fine which may extend to seven thousand rupees.

**Explanation.-** For the purpose of this section grievous injury shall include,-

- (i) emasculation (in the case of male camel),
- (ii) permanent privation of sight of either eye,
- (iii) permanent privation of the hearing of either ear,
- (iv) privation of any member or joint,
- (v) fracture or dislocation of a bone or tooth,
- (vi) any hurt that endangers life or which causes the sufferer severe bodily pain and ultimately renders unfit or unserviceable.

(2) Whoever abets the commission of an offence under subsection (1) shall be guilty of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided for the said offence.

**11. Burden of proof.-** Where any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that

he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

**12. Power to enter and inspect places.-** (1) For the purpose of this Act the Competent Authority or any person authorized in writing in that behalf by the Competent Authority (hereinafter in this section referred to as “the authorized person”) shall have power to enter and inspect any place where the Competent Authority or the authorized person has reason to believe that an offence under this Act has been, or is likely to be committed.

(2) Every person in occupation of such place shall allow the Competent Authority or the authorized person such access to that place as may be necessary for the aforesaid purpose and shall answer to the best of his knowledge and belief any question put to him by the Competent Authority or the authorized person.

(3) For the purpose of enforcing the provisions of this Act, the Competent Authority or the authorized person, in exercising the powers of entry upon, and inspection of, any place under this section, follow, as far as may be, the provisions of section 100 of Code, relating to the search or inspection of a place by a Police Officer.

**13. Person exercising powers under this Act deemed to be public servant.-** All persons exercising powers under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

**14. Protection of persons acting in good faith.-** No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which in good faith is done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

**15. Power to make rules.-** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules generally for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two

successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

---



**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

The Article 51A (g) of Constitution of India enjoins to have compassion towards all living beings.

Camel is an integral part of the desert eco-system of the State and has played a very important role in the survival of human population in adverse desert conditions. Presently, Camel is presently endangered and in need for initiation of sincere efforts for its conservation and protection, due to an alarming steep population decline observed in the recent past.

Several cases of intentional killings of camel and its progeny have come to light. It has also been observed that a large number of camels are transported or carried out of the State of Rajasthan to other States for the purpose of slaughter. The recurrent famine and scarcity conditions in the State tend to increase this menace all the more. The existing laws are not sufficient to tackle this problem.

Agriculture being the main stay of our economy, camel as a working animal is also the backbone of our agricultural and village economic structure. With growing awareness for non-conventional energy sources like biogas, the requirement of dung of these animals has acquired additional importance apart from its utility as manure and as a fuel for the rural population. Looking to the above factors, aged camels, even when they cease to be capable of yielding milk or working as draught animal can no longer be said to be useless or unfit.

In order to protect and improve the natural environment by minimising dependence on chemical fertilisers and pesticides, and by using natural and soil friendly manure generated as a biological phenomenon by these camelus animals, as also to have compassion for such useful living creatures as envisaged in Article 51A (g) of the Constitution, the slaughtering of these animals needs to be strictly prohibited to implement the spirit of aforesaid article of the Constitution.

Looking to the social, cultural and economic usefulness and contribution of camels, and to ensure their conservation, it is therefore, in general interest to enact a fresh law to prohibit the slaughter of camels as also to prohibit the export of such animals for the purposes of slaughter and to regulate, for other purposes,

the temporary migration or export of such animals in order to safeguard the camel species and also the interests of public deriving benefit from them.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

प्रभूलाल सैनी,  
Minister Incharge.

**संविधान के अनुच्छेद 304 के खण्ड (ख) के परन्तुक के अधीन  
महामहिम राष्ट्रपति महोदय की सिफारिश।**

(प्रतिलिपि: संख्या प.2 (29) विधि/2/2014 दिनांक 22 मार्च,  
2015 प्रेषक: प्रभूलाल सैनी, प्रभारी मंत्री, प्रेषित: विशिष्ट सचिव,  
राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के राष्ट्रपति महोदय ने राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात भारत के संविधान के अनुच्छेद 304 के खण्ड (ख) के परन्तुक के अनुसरण में उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने का अनुमोदन किया है।

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED  
LEGISLATION**

Clause 5 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the manner in which a permit or a special permit for temporary migration or export of camels may be issued.

Clause 15 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules for the purpose of carrying out the purposes of the Act.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

प्रभूलाल सैनी,  
**Minister Incharge.**

2015 का विधेयक सं.16

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात  
का विनियमन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

ऊंट के वध के प्रतिषेध हेतु उपबंध करने और उसके राजस्थान से अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

पृथ्वी राज,  
विशिष्ट सचिव।

(प्रभूलाल सैनी, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 16 of 2015

**THE RAJASTHAN CAMEL (PROHIBITION OF  
SLAUGHTER AND REGULATION OF TEMPORARY  
MIGRATION OR EXPORT) BILL, 2015**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**



RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

---

*A*

*Bill*

*to provide for prohibition of slaughter of camel and also to regulate temporary migration or export thereof from Rajasthan.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

PRITHVI RAJ,  
**Special Secretary.**

(Prabhu Lal Saini, **Minister-Incharge**)